International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 01(III), January - March, 2023, pp. 144-151

# सूचना–प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल इंडिया की अवधारणा : एक अध्ययन

डॉ. दिनेश कुमार गहलोत*
भावना भाटी**

***सार***

*डिजिटल इंडिया एक अभियान है जिससे सरकार की सेवाएं बेहतर ऑनलाईन माध्यम से तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। डिजिटल पहुँच को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के हर एक कोने तक पहुँचाना है। डिजिटल इंडिया के रूप में चलाए जा रहे कार्यक्रमों तथा योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाया जा रहा है। निरन्तर प्रयास से भारत के प्रत्येक क्षेत्र तक डिजिटल इंडिया की पहुंच होगी तथा भारत का डिजिटल रूप से सतत् विकास होगा।*

***शब्दकोशः*** *डिजिटल इंडिया, इंटरनेट, ई–गवर्नेंस*

---

**प्रस्तावना**

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसके उद्देश्य सरकारी विभागों को देश की जनता तक सरकारी सेवाएँ बिना कागज के इस्तेमाल के इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुचाना है। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को उच्च गति के इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया अभियान सूचना प्रौद्योगिकी की ताकत के जरिये भारत को बदलने की पहल है। इसका उद्देश्य किफायती, विकासात्मक और समावेशी तकनीक का इस्तेमाल कर गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाना है। सूचना प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित होने वाली 'मुख्य तकनीक' है। सभी विकासशील तथा विकसित देशों ने सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को मान्यता दी है तथा इसके प्रसार को बढ़ाने हेतु विभिन्न नीतियों का उपयोग व संयुक्त रूप से सार्वजनिक तथा निजी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सभी देशों में वृहत आर्थिक निर्णय व नियोजन, लोक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, विनिर्माण, वित्त तथा बैकिंग, परिवहन, वाणिज्य, प्रकाशन, ऊर्जा सरंक्षण तथा पर्यावरणीय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं।

डिजिटल इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम भारत के नागरिकों को सरकार द्वारा आसानी से ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने तथा इंटरनेट वेब और ऑनलाइन कार्य को सशक्त बनाकर भारत के तकनीकी और ऑनलाइन पहलुओं में सुधार करने के लिए है :–

डिजिटल इंडिया अभियान के तीन महत्वपूर्ण पहलू है –

- डिजिटल इंफ्रास्ट्रचर
- डिजिटल रूप से सेवाएँ प्रदान करना
- डिजिटल साक्षरता

डिजिटल इंफ्राइस्ट्रचर से तात्पर्य है जहां सभी पंजीकृत नागरिकों की डिजिटल पहचान होगी, जो सुरक्षित और तेज सरकारी सेवाएं प्राप्त करने में मदद होगी।

---

* सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।
** शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

सभी सरकारी सेवाएं जैसे बैंक खाते का प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा आदि जिन्हें अब उपयोग करना बहुत आसान बनाया जा सकता है और जो साइबर–अपराध से सुरक्षित होगा।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आईटी नौकरियां भी प्रदान करना है क्योंकि यह कार्यक्रम डिजिटल विकास पर जोर देता है। यह पीढ़ी के युवाओं को क्षेत्र में समान रूप से रोजगार प्रदान करेगा जिससे समाज में बेरोजगारी की समस्या भी कम होगी।

भारत सरकार ने 2006 में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (NEGP) शुरू की। विभिन्न डोमेन को कवर करते हुए 31 मिशन मोड परियोजनाएँ शुरू की। देश में कई ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के बाद भी सभी उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। [1]

देश को डिजिटल रूप से विकसित करने के लिए सूचना तथा सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा विभिन्न कदम उठाये गए। 1 लाख करोड़ रूपये से अधिक डिजिटल इंडिया अभियान की विभिन्न योजनाओं जैसे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को लॉन्च करके कार्यक्रम का अनावरण किया। पोर्टल, स्वास्थ्य शिक्षा, डिजिटल लॉकर और कई सरकारी कार्यक्रम जैसे आधार कार्ड आदि ऑनलाइन हो गए। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं के पूरे परिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से आम नागरिकों की सभी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आसान किया गया है। डिजिटल रूप से नागरिकों के कार्यों को सरल बनाया गया है तथा सरकार का उद्देश्य यह भी रहा है कि प्रत्येक गांव के नागरिकों तक यह सुविधा आसानी से पहुंचे। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम भी किए गए। अभी भी कई ऐसे गांव इस सुविधा से वंचित रह गए है तथा सरकार जल्द ही वहां तक भी इस सुविधा को पहुंचने में प्रयत्न अग्रसर करेगी।

**डिजिटल इंडिया की पहल [2]**

- My Gov. **मेरी सरकार –** डल ळवअण् प्लेटफॉर्म एक अनूठी पथ प्रदर्शक पहल है जिसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह आम नागरिक को शामिल करते हुए अपनी तरह की अनूठी पहली भागीदारीपूर्ण शासन पहल है। डल ळवअण् का विचार भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में योगदान करने के अंतिम लक्ष्य के साथ आम नागरिक और विशेषताओं को शामिल करते हुए विचारों और विचारों के स्वस्थ आदान – प्रदान के लिए एक इंटरफेस बनाने वाले ऑनलाइन प्लटेफार्म के उपयोग से सरकार को आम आदमी के करीब लाता है। वेबसाइट – http://mygov.in

**आईसीटी का उपयोग करते हुए शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन**

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन (एनएईआईसीटी) को किसी भी समय किसी भी मोड में उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी विद्यार्थियों के लाभ के लिए शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है। यह छात्रों, शिक्षकों और आजीवन शिक्षार्थियों की शिक्षा और सीखने से संबंधित सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक ऐतिहासिक पहल है। वेबसाईट – http://www.nmeict.ac.in/#

- **नरेगा सॉफ्ट –** नरेगा सॉफ्ट राज्य, जिले और पंचायती राज संस्थानों के तीन स्तरों में ई–गवर्नेंस को लागू करने की कल्पना करता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एक सुविधाकर्ता के रूप में आम आदमी को सशक्त बनाता है। नरेसा सॉफ्ट सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुपालन में नागरिकों को सूचना प्रदान करता है। यह मास्टर रोल, पंजीकरण, आवेदन रजिस्टर, जॉब कार्ड/रोजगार रजिस्टर/इश्यू रजिस्टर, मस्टर रोल, रसीद रजिस्टर जैसे सभी दस्तावेज उपलब्ध कराता है जो अन्यथा जनता से छिपाए जाते हैं। वेबसाईट – http://www.nrega.net/ict/

**प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)**

PMGDISHA, 31 मार्च 2019 तक प्रत्येक पात्र से एक सदस्य को कवर करके ग्रामीण क्षेत्रों में, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में छह करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने, लगभग 40 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक पहुंचने की एक योजना है। इसका उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटना है। विशेष रूप से अनुसूचित

जाति (एएसी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी), अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), महिलाओं और अलग–अलग विकलांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों जैसे समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गो सहित ग्रामीण आबादी का लक्षित करना। वेबसाईट – http://www.pmgdisha.in/

**डिजिधन अभियान**

इस पहल की योजना नागरिकों और व्यापारियों को डिजिधन बाजार के माध्यम से वास्तविक समय में डिजिटल लेन–देन करने में सक्षम बनाने की है। देश भर में डिजिधन मेला आयोजित करने के माध्यम से इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को डिजिटल लेन–देन करने के लिए विभिन्न डिजिटल भुगतान प्रणालियों को डाउनलोड करने स्थापित करने और उपयोग करने में मदद करना है। वेबसाईट – http://digidhan.mygov.in/

**प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई)**

यह वित्तीय समावेशन में एक राष्ट्रीय मिशन है। इस योजना के अन्तर्गत हर घर में कम से कम एक बैंक खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुँच, बीमा और पैंशन सुविधा तक पहुँच की परिकल्पना की गई है। इस पहल में सभी सरकारी लाभों को लाभार्थियों के खातों में तथा केन्द्र सरकार के प्रत्यक्ष लाभ योजना को आगे बढ़ाने की परिकल्पना है। वेबसाईट – http://pmjdy.gov.in/

इसी प्रकार सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के अन्तर्गत कई पहलें की गई है जिससे सभी नागरिकों को डिजिटल कार्यक्रमों से अवगत कराया जाए तथा उनके सभी कार्यो को डिजिटल रूप में करा कर सरल किया जाए।

**स्मार्टसिटीज**

भारत सरकार ने जून 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य नागरिकों को एक अच्छी गुणवत्ता, स्वच्छ और टीकाऊ वातावरण और 'स्मार्ट' समाधानों को प्रदान करना है। शहरों को सतत् तथा स्मार्ट विकास करना है। स्मार्ट सिटीज मिशन के द्वारा स्मार्ट सिटी के भीतर और बाहर दोनों जगह स्मार्ट बनाना है, देश के सभी क्षैत्रों और हिस्सों में समान स्मार्ट शहरों के निर्माण को उत्प्रेरित किया जा सकता है। वेबसाईट – http://smartcity.gov.in/content/

**डिजिटल सेवाएँ**

डिजिटल सेवाएँ सभी आम लोगों को पोर्टल या उमंग मोबाइल ऐक के जरिये आम लोगों को आसानी से उपलब्ध कराई जाती है। डिजिटल सेवाओं का वर्णन इस प्रकार है :–

**राष्ट्रीय छात्रवृत्ति**

यह पोर्टल छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति संबंधी सभी जरूरतों के लिए एक जगह है। राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के मिशन मोड प्रोजेट का उद्देश्य देश भर में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा शुरू की गई विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करने के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है।[3]

**जीवण प्रमाण**

आधार डिजिटल पहचान का इस्तेमाल कर पेंशनभोगियों की जांच – पड़ताल में सरलता के लिए है। 2004 से अब तक 1.73 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सौंपे जा चुके है। मरीजों के लिए डॉक्टरों की उपलब्धता आसान हो सके, इसके लिए ई–अस्पताल और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेवाएँ शुरू की गई। इसे 318 अस्पतालों में लागू किया गया है।

**डिजिलॉकर**

डिजिलॉकर के द्वारा भारत के कागत रहित शासन की ओर कदम बढ़ाए है। डिजिलॉकर एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है, जो लोगों और संस्थाओं को अपने सभी कानूनी दस्तावेजों को जारी करने, प्रमाणित करने, संग्रहित करने तथा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। डिजिटल लॉकर के उपयोग से दस्तावेजों को सुरक्षित ऑनलाइन रखा

जा सकता है। उपयोगकर्ता को इन्हें साझा करने से पहले दस्तावेज पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने की सुविधा मिलती है जिससे कागजी दस्तावेजों को जमा कराने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तथा उपयोगकर्ता फोन के जरीये पंजीकरण कर, अपने आधार कार्ड को इसके साथ लिंक कर दस्तावेज अपलोड़ कर सकते है।

**ई–वीजा**

ई–वीजा की सेवाओं के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसमें किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं होती है। 24 हवाई अड्डों और 5 समुद्री बंदरगाहों पर 163 देशों से आने वाले पर्यटकों के लिए ई–पर्यटक वीजा की प्रणाली शुरू की गई है।

**ई–अदालत**

ई–अदालत मोबाइल ऐप और पोर्टल के जरिये देशभर की विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों की स्थिति की निगरानी रखना आसान हो गया है। वकील और मुकदमेंबाज़ अपने मुकदमों के बारे में जानकारियों को प्राप्त करने का लाभ उठा सकते है।

**मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना**

इस योजना को 19 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य मृदा परीक्षण आधारित और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है ताकि किसान कम लागत पर अधिक उपज प्राप्त कर सकें।

**डिजिटल भारत के प्रमुख 9 स्तम्भ निम्न प्रकार है [4]**

- ब्रॉडबैंड हाईवे
- मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुँच
- पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम
- ई–गवर्नेंस – प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार
- ई–क्रांति – सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी
- सभी के लिए सूचना
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
- नौकरियों के लिए आईटी
- अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम/प्रारंभिक फसल कार्यक्रम

**ब्रॉडबैंड हाईवे**

इस योजना के अन्तर्गत सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ना है। सामान्य तौर पर ब्रॉडबैंड का अर्थ दूरसंचार से होता है, जिससे सूचना के संचार के लिए आवृत्तियों के व्यापक बैंड उपलब्ध होते हैं। इससे सूचना को कई गुणा तक बढ़ाया जा सकता है और जुड़े हुए तमाम बैंड की विभिन्न आवृत्तियों या चैनलों के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसके माध्यम से समय सीमा के अन्तर्गत सूचनाओं को प्रेषित किया जा सकता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे किसी राजमार्ग पर एक से ज्यादा होने स उतने ही समय में ज्यादा गाड़ियां आवाजाही कर सकती है। ब्रॉडबैंड राजमार्ग के निर्माण से 2018 तक पूरे देश के करीब ढ़ाई लाख गांव पंचायतों को इस योजना से जोड़ने का कार्यक्रम है। इस योजना से गांव में इंटरनेट होने से सभी नागरिकों को सरकारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो तथा उनके कार्य इंटरनेट के द्वारा ही सम्पन्न हो जाएगें।

**मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुँच**

पूरे भारत में तकरीबन एक अरब 25 लाख की आबादी में मोबाइल फोन कनेक्शन की संख्या जून 2014 तक करीब 80 करोड़ थी। शहरी इलाकों तक भले ही मोबाइल फोन पूरी तरह से सुलभ हो गया हो, लेकिन देश के

विभिन्न ग्रामीण इलाकों में अभी भी इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। मोबाइल संपर्क की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस अब्लिगेशन फंड का गठन किया गया है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को आसानी से इंटरनेट और मोबाइल बैकिंग के इस्तेमाल की सुविधा उपलब्ध होगी।

### पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम

पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम के दो उप–घटक लोक सेवा केन्द्र और बहुउद्देश्य सेवा केन्द्र के रूप में डाकघर हैं। डिजिटल इंडिया के तहत लोक सेवा केन्द्रों को और मजबूत किया जाएगा और इसकी संख्या 1,35,000 से बढ़ाकर लगभग 2,50,000 की जाएगी अर्थात् प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक लोक केन्द्र (सीएससी) की स्थापना की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए डाक विभाग को नोडल विभाग के रूप में अधिकृत किया गया है।

### ई–गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से शासन में सुधार

सरकारी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में लेन–देन में सुधार के लिए सभी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इसमें सभी विभागों में ऑनलाइन आवेदन को बढ़ावा देना, स्कूल प्रमाण–पत्रों एवं मतदाता पहचान पत्र, आधार, भुगतान, मोबाइल प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज आदि की ऑनलाइन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है।

### ई–क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी

ई–क्रान्ति के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मौलिक अधिकारों और वित्तीय अधिकारों जैसी सेवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया। किसानों के लिए सही समय के महत्व की सूचना, नकदी कर्ज रहित भुगतान, मोबाइल बैकिंग आदि की ऑन लाइन सेवा करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑनलाइन डॉक्टरी सलाह, रिकॉर्ड और संबंधित दवाओं के आपूर्ति समेत मरीजों की सूचना से संबंधित एक्सचेंज की स्थापना करते हुए लोगों को ई–हेल्थकेयर की सुविधा देना, न्याय के क्षेत्र में ई–कोर्ट, ई–पुलिस, ई–प्रोसिक्यूशन की सुविधा, वित्तीय प्रबंधन के मोबाइल बैकिंग तथा माइक्रो–एटीम प्रोग्राम उपलब्ध कराना आदि इसमें सम्मिलित हैं।

### सभी के लिए सूचना

यह ऑनलाइन इंटरनेट वेबसाइट और सोशन मीडिया और वेब आधारित सिस्टम जैसे डल ळवअण के माध्यम से सभी नागरिकों को वास्तविक जानकारी प्रदान करने पर क्रेन्दित है।

### इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

इसके तहत कंटेनर, वीसैट, मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आधुनिक बिजली मीटर, स्मार्ट कार्ड और माइक्रो एटीएम के निर्माण पर फोकस किया गया है। भविष्य में स्थानीय उत्पादकों को कर छूट और लागत लाभ छूट भी दे सकता है।

### नौकरियों के लिए आईटी

देशभर में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार से रोजगार के अधिकांश प्रारूपों में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। कौशल विकास के मौजूदा कार्यक्रमों को भी इस प्रौद्योगिकी से जोड़ने की योजना है। गांवो व छोटे शहरों में लोगों को आईटी से जुड़े नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया गया। आईटी सेवाओं से जुड़े कारोबार के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए दूरसंचार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

### अर्ली हार्पेस्ट प्रोग्राम

इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ नियमों का निर्माण किया है जो देश में लागू किए गए। सर्वप्रथम सूचनाओं के लिए आईटी प्लेटफॉर्म बनाए जाएगें। सभी विभागों में बायोमैट्रिक्स उपस्थिति की सुविधा लागू की गयी तथा देश के सभी विश्वविद्यालयों में वाई–फाई/सरकारी ई–मेल की सुविधा प्रदान की गयी। मौसम विभाग द्वारा मोबाइल से आपदा की चेतावनी देने के लिए टीम गठित की गयी तथा सभी छात्रों के लिए किताओं का ई–बुक बनाया गया।

**डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तीन प्रमुख दृष्टि क्षेत्र पर केन्द्रित है [5]**

- **प्रत्येक नागरिक के लिए एक प्रमुख उपयोगिता के रूप में डिजिटल संरचना**
  - नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रमुख उपयोगिता के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना।
  - प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट आजीवन, ऑनलाइन और प्रमाणित की जा सकने वाली डिजिटल पहचान उपलब्ध करना।
  - मोबाईल फोन और बैक खाता डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में नागरिकों की भागीदारी को सक्षम बनाता है।
  - किसी सामुहिक सेवा केन्द्र तक आसान पहुँच करना।
  - सुरक्षित साइबर स्थान की व्यवस्था करना।
- **नागरिकों की माँग पर शासन और सेवाएं**
  - सभी विभागों एवं क्षेत्राधिकारों में एकीकृत सेवाएँ प्रदान करना।
  - ऑनलाइन एवं मोबाइल प्लेटफॉर्मों से वास्तविक समय सेवाओं को उपलब्ध कराना।
  - व्यवसाय में सुधार लाने के लिए सेवाओं का डिजिटल रूप में रूपान्तरण करना।
  - वित्तीय लेन–देन को इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस बनाना।
  - सभी नागरिकों की पात्रता संबंधी विवरणों को आसान पहुँच के साथ क्लाउड पर उपलब्ध कराना।
  - निर्णयन समर्थन प्रणाली और विकास हेतु भूस्थानिक सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग करना।
- **नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना**
  - सार्वभौमिक रूप से सुलभ डिजिटल संसाधन
  - सभी दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर उपलब्ध कराना।
  - भारतीय भाषाओं में डिजिटल संसाधनों/सेवाओं की उपलब्धता।
  - सहभागी शासन हेतु सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित करना।

रोजगार, उद्यमिता और सशक्तिकरण के लिए डिजिटल इंडिया[6]

**घर के पास डिजिटल सेवा प्रदान करना (आम सेवा केन्द्र)**

ग्रामीण इलाकों में उचित दर पर डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश भर के 2.10 लाख ग्राम पंचायतों में 3.06 लाख से भी ज्यादा डिजिटल सेवा केन्द्रों का विशाल नेटवर्क तैयार किया गया है। इन केन्द्रों के जरिये 12 लाख रोजगार पैदा हुए तथा ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा मिला है और इस तरह से वंचित तबकों के सशक्तीकरण की राह आसान बनी है। जिन ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा मिला है, उनमें 61,055 महिलाएँ हैं। आम सेवा केन्द्रों ने ग्रामीण महिलाओं के बीच माहवारी से जुड़े स्वास्थ्य और सफाई के लिए जागरूकता फैलाने की खातिर स्त्री स्वाभिमान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में सैनिटरी पैड बनाने वाली कई छोटी–छोटी इकाइयाँ खोली गई है। इन इकाइयों ने न सिर्फ ग्रामीण महिलाओं को आजीविका का अवसर मुहैया कराया है, बल्कि स्थानीय स्तर पर सस्ते सैनिटरी पैड की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है।

**देश में आम लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना**

देश में हर घर में एक शख्स को ई–साक्षर बनाने के उद्देश्य से दो योजनाएँ एनडीएलएम और दिशा शुरू की गई। इसके तहत देश में कुल 53.7 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया और डिजीटल साक्षरता का प्रमाण–पत्र दिया गया। पुरानी योजनाओं की तर्ज पर सरकार ने ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता के प्रचार–प्रसार के लिए नई योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) को मंजूरी दी है। इसके दायरे में 6 करोड़

ग्रामीण घरों को शामिल किया गया है। अब तक कुल 1.47 करोड़ उम्मीदवारों का प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत नामांकन हो चुका है और इनमें से 1.43 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। जबकि 74.5 उम्मीदवारों को प्रमाण–पत्र दिए गए हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता मिशन है।

### मेक इन इंडिया के लिए डिजिटल इंडिया – इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा

भारत सरकार ने आयात घटाने के उद्देश्य से देश में इलेक्ट्रोनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की पहल की है। मोबाइल फोन के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका मकसद भारत में मोबाइल हैंडसेट और कंपानेंट विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक और गहरा बनाना हैं।

### नई तकनीकों से संबंधित पहल

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), इंटर्नल सिक्योरिटी, बौद्धिक संपदपा अधिकार (आईपीआर), नेत्रहीनों के लिए स्पर्श संबंधी ग्राफिक, कृषि और पर्यावरण, ईएसडीएम, फिटनेक, भाषा तकनीक, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल टेक और हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, ब्लॉकचेन, गेमिंग व एनिमेशन और बायोमेटिक के क्षेत्रों में 20 उत्कृष्टता के केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजीटल पहचान मुहैया कराने, डिजीटल आधारभूत संरचना तैयार करने, सेवाओं की डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित करने और रोजगार व उद्यम संबंधी अवसर को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न उपाय किए गए है। इन उपायों ने भारत को डिजिटल सम्पन्न समाज में बदल दिया है और आम नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। डिजिटल अभियान की संभावनाओं के इस्तेमाल और इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पहचान बेहत जरूरी है। अलग डिजिटल पहचान मुहैया कराने के लिए देश के तकरीबन 122 करोड़ लोगों को आधार से जोड़ा गया है। सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं की डिलीवरी और सुलभता के लिए लोगों की वास्तविक पहचान के पूरक के तौर पर डिजिटल पहचान जरूरी कराया है। इससे सार्वजनिक कल्याण की प्रणाली से भ्रष्ट गतिविधियों को रोक सकते है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में न सिर्फ आधार की संवैधानिक वैद्यता को सही ठहराया, बल्कि इसे गरीब लोगों के सशक्तीकरण का औजार भी बताया।

### डिजिटल इंडिया के सकारात्मक पहलू

कोविड–19 महामारी के दौरान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की भूमिकाः

- कोविड–19 स्थिति के समय डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आरोग्य सेतु को 3 सप्ताह में 12 भारतीय भाषाओं के साथ विकसित किया गया है जिसे अब तक लगभग 13 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। इस एप ने 350 से अधिक कोविड–19 हॉटस्पोट की पहचान करने में मदद की।
- कोविड–19 से निपटने हेतु सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स, वीडियो, उद्धरणों के माध्यमों के द्वारा नागरिकों को जागरूक करने में डलहवअ वेबसाइट और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया चैनलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- कोविड–19 के समय सभी ट्राँजेक्शन डिजिटल माध्यम से किये जाते थे जैसे बिजली–पानी बिल, मोबाइल बिल, घरेलु आवश्यक सामग्री आदि प्रकार के ट्रांजेक्शन डिजिटल माध्यम से आसानी से किए जाते थे।
- कोविड–19 के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों द्वारा पढ़ाई को ऑनलाईन मोड पर स्थानान्तरित कर दिया गया था।
- प्रधानमंत्री ने लोगों के कोरोना सम्बन्धी प्रश्नों के समाधान हेतु व्हाट्सएप चैटबोट से जुड़ने की घोषणा की थी।
- कोविड–19 महामारी के दौरान प्रभावित लोगों तक प्रशासनिक मदद व खाद्य सामग्री पहुँचाने का कार्य प्रभावी रूप से डिजिटल माध्यम के द्वारा किया जा रहा है।

## डिजिटल इंडिया की चुनौतियाँ

- डिजिटल इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि डिजिटल इंडिया सुविधा को देश के हर एक घर तक पहुँचाने की बात थी लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ तक यह सुविधा अब तक नहीं पहुँच पायी।
- ग्रामीण जनता का शिक्षित न होना, जहाँ डिजिटल पहुँच है वहां एक समस्या यह रहती है कुछ ग्रामीणों के पास यह सुविधा है तो उन्हें सुविधाओं का लाभ उठाना नहीं आता उन्हें डिजिटल साधनों का उपयोग करने हेतु शिक्षित होना आवश्यक है।
- भारत में इंटरनेट की गति अन्य प्रमुख देशों की तुलना में काफी कम है।
- डिजिटल इंडिया की सफलता में साइबर सुरक्षा व डेटा सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन भारत में साइबर खतरा व डेटा लीक की समस्या ज्यादा देखी जा रही है तथा अभी इससे संबंधित कोई कानून नहीं है इसलिए डिजिटल इंडिया को अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है।
- भारत में सीमित संसाधनों के कारण हाईस्पीड इंटरनेट देश के अधिकांश हिस्सों तक पहुंचने में समय लग रहा है।

## निष्कर्ष

डिजिटल इंडिया ने भारतीय नागरिकों के लिए आवश्यक सरकारी सुविधाओं को सरल बना दिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी अधिक लाभ होगा। सरकार और देश के नागरिक एकजुट होकर लक्ष्य हासिल कर सकते है, जिससे यह सुनिश्चित कर सकते है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम देश को आने वाले समय में डिजिटल तौर पर विकसित राष्ट्र बनाएगा। आम नागरिकों को डिजिटल इंडिया के अन्तर्गत सभी सुविधाओं को आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को इसके लक्ष्य तक पहुँचाने में हालांकि बहुत सारी चुनौतियां राह में खड़ी हैं, फिर भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की व्यक्तिगत पहल और निगरानी से इन विभिन्न योजनाओं का उभरते भारत में सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगा है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. www.digitalindia.gov.in
2. www.digitalindia.gov.in
3. www.scholarships.gov.in
4. www.digitalindiainsight.com
5. राय, गांधीजी, नरेन्द्र मोदी की शक्तिशाली भारत की संकलपना – डिजिटल इण्डिया मिशन एवं विविध योजनाऐं, लोकप्रशासन जनवरी–जून, 2018, पृष्ठ संख्या 2–3, सम्पादक – प्रो. एस.एन. मिश्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, अर्द्ध वार्षिक शोध पत्रिका
6. प्रसाद, रविशंकर, डिजिटल भारत : समावेशीय एवं सशक्त भविष्य की राह, योजना, दिसम्बर 2016, पृष्ठ सं. 10, feias.com

❖◆❖